# 1

1.1 वैश्विक समष्टिगत वित्तीय परिस्थिति

1.2 घरेलू समष्टिगत आर्थिक प्रगति

1.3 कृषि में सुदृढ़ वृद्धि ने ग्रामीण माँग को बढ़ावा दिया

1.4 ग्रामीण आर्थिक गतिविधि जीवंत बनी रही

1.5 समष्टिगत आर्थिक दृष्टिकोण

अध्याय 1 का परिशिष्ट


# भारत और विश्व—वर्ष 2024–25 में अर्थव्यवस्था

भू-आर्थिक संघर्षों, उत्पादकता में कमज़ोर वृद्धि, अवस्फीति की रुकी हुई गति, ऋण के उच्च स्तरों और अस्थिर वित्तीय बाज़ारों के कारण आई शिथिलता की वजह से वर्ष 2024 में वैश्विक वृद्धि अपने दीर्घकालिक औसत से भी कम बनी रही. अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की नरम कीमतों के स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव के होते हुए भी, संरक्षणवादी टैरिफ़ (प्रशुल्क) में वृद्धि और बढ़ती अनिश्चितता ने वर्ष 2025 में वैश्विक वृद्धि के समक्ष जोखिमों को कई गुना बढ़ा दिया है.

चुनौती भरे वैश्विक समष्टिगत वित्तीय परिदृश्य के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2025 में अनुकूल वृद्धि दर्शाई. घरेलू मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी, पूँजीगत व्यय पर निरंतर राजकोषीय बल, कॉर्पोरेट घरानों के मजबूत तुलन-पत्रों, बाह्य संतुलन की सुदृढ़ स्थिति और एक स्थिर वित्तीय प्रणाली ने इसे सहारा दिया. कृषि में सुदृढ़ वृद्धि और ग्रामीण माँग की जीवंत परिस्थितियों ने विकास की गति को आधार प्रदान किया. आगे नज़र डालें तो, उदार मौद्रिक नीति, पर्याप्त तरलता की स्थितियों, विनियमन हटाने, और आयकर सुधारों के माध्यम से खपत की माँग को प्रोत्साहित करने पर लक्षित राजकोषीय उपायों से वित्तीय वर्ष 2026 में विकास की दर को सहारा मिलने की उम्मीद की जा सकती है. हालाँकि, अनसुलझे प्रशुल्क विवादों तथा बिगड़ती वैश्विक वृद्धि के स्पिलओवर से विकास के दृष्टिकोण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

## 1.1 वैश्विक समष्टिगत वित्तीय परिस्थिति

वर्ष 2024 में वैश्विक विकास दर 3.3% रही, जो वर्ष 2000 से वर्ष 2019 के दौरान दर्ज 3.7% की दीर्घकालिक औसत वृद्धि से कम थी (तालिका 1.1). वर्ष 2025 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2025 में किए गए आकलन के अनुसार संरक्षणवादी प्रशुल्कों में वृद्धि और अत्यधिक अनिश्चितता के परिणामस्वरूप उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) और उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) दोनों को प्रभावित करते हुए वैश्विक विकास दर घटकर 2.8% की होने का अनुमान है. वैश्विक व्यापार नीति अनिश्चितता सूचकांक, रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गया, जो वर्ष 1960 के बाद से अब तक नहीं देखा गया था. वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक कोविड-19 महामारी के दौरान देखे गए स्तरों के करीब पहुँचकर नए शिखरों पर पहुँच गया. बॉण्ड, इक्विटी और विदेशी मुद्रा बाजार भी समय-समय पर अस्थिरता के दौरों से गुजरे.

वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर अनुभव की गई उल्लेखनीय अवस्फीति, जिसने तेज ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें बढ़ा दीं, के बाद अवस्फीति की गति काफी धीमी हो गई और वर्ष 2025 की पहली तिमाही में अधिकांश देशों में सकल मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति के लक्ष्यों से ऊपर रहने लगी. व्यापार संबंधी तनावों के हल होने तक मुद्रास्फीति और विकास के प्रति देशों के दृष्टिकोण अनिश्चित होते गए, व्यापार में कम होते विश्वास के बीच वित्तीय बाज़ार धार पर बना रहा.

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार, वैश्विक माल व्यापार की मात्रा वर्ष 2024 की क्रमिक तिमाहियों और वर्ष 2025 के शुरुआती महीनों में स्थिर गति से बढ़ी, किंतु उसके बाद, विशेष रूप से प्रशुल्कों की लहर और परवर्ती चयनात्मक अस्थायी आस्थगन के चलते, माल का व्यापार वर्ष 2025 में 0.2% से संकुचित होने का अनुमान है. यदि स्थिति और बिगड़ती है तो इस संकुचन में 1.5% की और वृद्धि हो सकती है. वर्ष 2024 में वैश्विक व्यापार में सेवाओं की हिस्सेदारी 26.4% थी, जिसने मात्रा की दृष्टि से हाल के वर्ष में माल व्यापार की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की. मूल्य की दृष्टि से 2024 में सेवा व्यापार में 9% की वृद्धि हुई, जबकि माल व्यापार में 2% की ही वृद्धि हुई. वर्ष 2025 में, कमजोर समग्र वैश्विक माँग के माध्यम से संचालित टैरिफों के अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण सेवाओं के व्यापार की वृद्धि में भी कमी होने की संभावना है. ऐसे माहौल में तेल और तेल से भिन्न, दोनों की पण्य कीमतें अस्थिर बनी रहीं. जहाँ अक्टूबर 2024 में और फिर जनवरी 2025 में कच्चे तेल (ब्रेंट) की कीमतें $80 प्रति बैरल से ऊपर पहुँच गईं, वहीं मार्च 2025 तक इसमें भारी गिरावट आई और मई 2025 की शुरुआत में कीमतें $60 प्रति बैरल के करीब पहुँच गईं. जून 2025 में छोटी सी अवधि के दौरान तेल की कीमतों में वृद्धि हुई, किन्तु नए भूराजनीतिक तनावों के कारण इन कीमतों में फिर से गिरावट आई. सोने की कीमतें वर्ष 2025 में नई ऐतिहासिक ऊँचाइयों पर पहुँच गईं.

### तालिका 1.1: वैश्विक आर्थिक संकेतक (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि %)

| संकेतक | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| विश्व आउटपुट | 3.3 | 3.3 | 2.8 |
| उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ (एई) | 1.7 | 1.8 | 1.4 |
| उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ (ईएमडीई) | 4.4 | 4.3 | 3.7 |
| विश्व व्यापार की मात्रा (माल और सेवाएँ) | 0.7 | 3.8 | 1.7 |
| विश्व व्यापार की मात्रा (माल) | -1.0 | 2.9 | -0.2 |
| विश्व व्यापार की मात्रा (वाणिज्यिक सेवाएँ) | 6.8 | 6.8 | 4.0 |
| विश्व उपभोक्ता मूल्य | 6.7 | 5.7 | 4.3 |
| एई | 4.6 | 2.6 | 2.5 |
| ईएमडीई | 8.1 | 7.7 | 5.5 |
| पण्य मूल्य ($) | | | |
| तेल | -16.4 | -1.8 | -15.5 |
| ईंधन से भिन्न | -5.7 | 3.7 | 4.4 |

स्रोत:

- आईएमएफ (2025), वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2025, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वॉशिंगटन, डी. सी. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2025/04/22/world-economic-outlook-april-2025.
- विश्व व्यापार की मात्रा (माल), विश्व व्यापार की मात्रा (वाणिज्यिक सेवाएँ): डब्ल्यूटीओ (2025), वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी, विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, अप्रैल. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_outlook25_e.pdf.

## 1.2 घरेलू समष्टिगत आर्थिक प्रगति

### 1.2.1 एक सुदृढ़ समष्टिगत आर्थिक नीति के परिवेश में अनुकूल वृद्धि

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि, सुदृढ़ घरेलू समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों के चलते वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान भी सुदृढ़ बनी रही. इसके प्रमुख कारकों में मुद्रास्फीति में कमी, सार्वजनिक क्षेत्र के पूँजीगत व्यय पर निरंतर बल, निरंतर राजकोषीय दृढ़ीकरण, चालू खाता घाटे के एक संधारणीय स्तर, वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता और मजबूत कॉरपोरेट तुलन-पत्र शामिल हैं. वित्तीय वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 6.5% रही, हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2024 में दर्ज की गई 9.2% की मजबूत वृद्धि से धीमी हो गई, किंतु भू-आर्थिक संघर्षों और व्यापारिक तनावों में वृद्धि से प्रभावित प्रतिकूल वैश्विक वातावरण के बीच भी भारत, विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा (चित्र 1.1).

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन द्वारा मापी जाने वाली मुद्रास्फीति, वर्ष के अंतिम दो माह में तेजी से घटकर 4% से भी नीचे आ गई और वर्ष के लिए औसत मुद्रास्फीति 4.6% रही, जो पिछले पाँच वर्षों में अनुभव की गई औसत मुद्रास्फीति से भी कम थी (चित्र 1.1). मौद्रिक नीति के फ़्लेक्सिबल इन्फ़्लेशन टार्गेटिंग (एफआईटी) फ्रेमवर्क के तहत मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं के मजबूत कसाव के साथ-साथ, मौद्रिक नीति के पूर्व में सख्त होने और राजकोषीय समेकन के सहारे मूल सीपीआई (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) मुद्रास्फीति पूरे वर्ष मंद बनी रही. वर्ष की अंतिम तिमाही में मुद्रास्फीति में वैविध्यपूर्ण नरमी और वित्तीय वर्ष 2026 में मुद्रास्फीति के लिए संशोधित नरम दृष्टिकोण के साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक ने नीतिगत दर को संचयी रूप से 100 आधार अंक कम कर दिया और प्रणाली में पर्याप्त तरलता उपलब्ध कराई, ताकि प्रणाली में समग्र तरलता की स्थिति को एक अधिशेष के रूप में परिवर्तित किया जा सके. इससे पूरी मीयादी संरचना में ब्याज़ की दरों को कम करने में सहायता मिली.

भारत के बाह्य संतुलन की स्थिति सुदृढ़ बनी रही. वर्ष 2024-25 में $23.3 बिलियन (जीडीपी का 0.6%) चालू खाता घाटा वर्ष 2023-24 के $26.0 बिलियन (जीडीपी का 0.7%) से कम था. जबकि वास्तव में वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में भारत के चालू खाता शेष में $13.5 बिलियन का आधिक्य दर्ज किया गया था. माल व्यापार के लिए एक प्रतिकूल वैश्विक वातावरण के बावजूद वर्ष के दौरान उच्चतर सेवा निर्यातों और धनप्रेषण आगमों से चालू खाता घाटे को नियंत्रित करने में सहायता हुई.

## चित्र 1.1: प्रमुख समष्टिगत आर्थिक रुझान

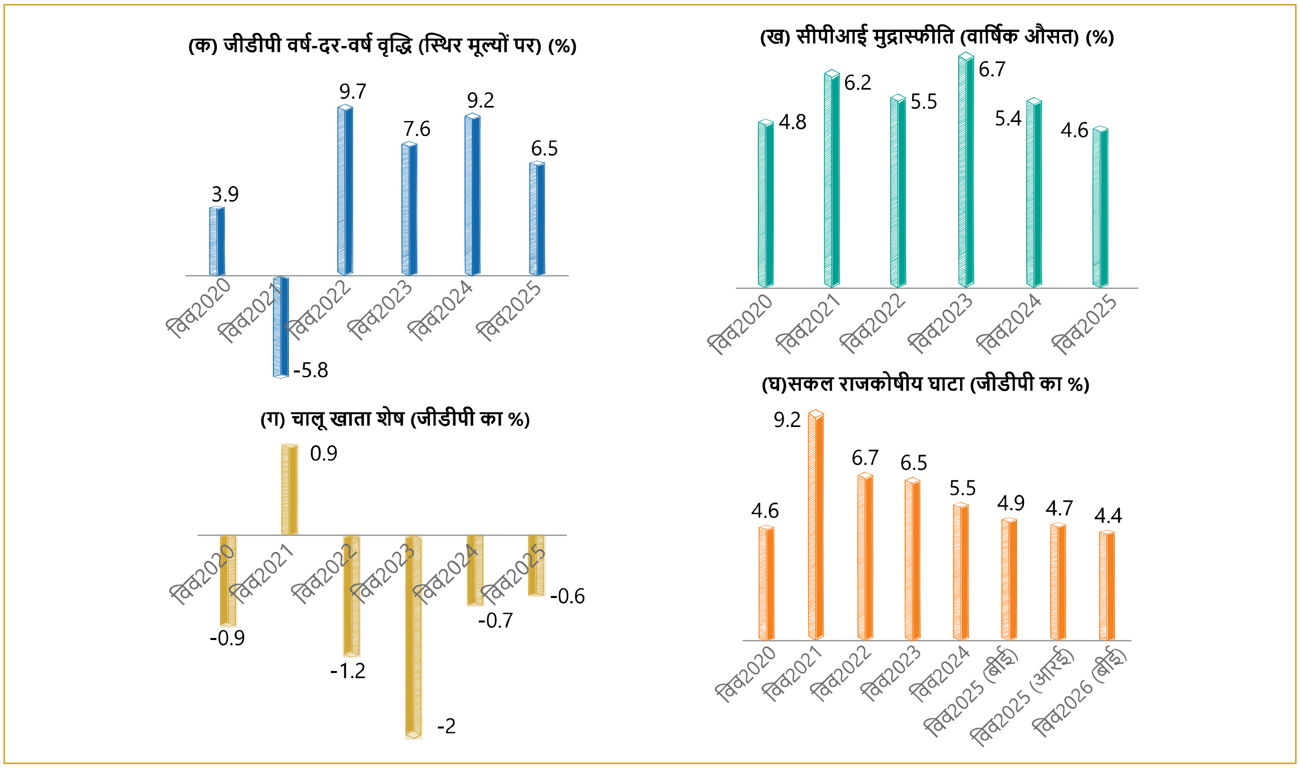


बीई = बजट अनुमान, सीपीआई = उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आरई = संशोधित अनुमान, जीडीपी = सकल घरेलू उत्पाद

*नोट:* चित्र 1.1(घ) में राजकोषीय आँकड़े जीडीपी आँकड़ों में संशोधनों के कारण केंद्रीय बजट में प्रकाशित आँकड़ों से भिन्न हो सकते हैं.

स्रोत:

- चित्र 1.1 (क): भारत सरकार (2025), वर्ष 2024-25 हेतु वार्षिक जीडीपी के अनंतिम अनुमान और वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही हेतु जीडीपी का त्रैमासिक अनुमान, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2132688.
- चित्र 1.1 (ख): भारत सरकार (विभिन्न वर्ष), केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार.| भारतीय रिजर्व बैंक (2025), मौद्रिक नीति विवरणियाँ (2024-25), भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई.
- चित्र 1.1 (ग): भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस, भारतीय रिजर्व बैंक. https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/home.
- चित्र 1.1 (घ): केंद्रीय बजट, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार.

राजकोषीय नीति ने लक्षित सार्वजनिक व्यय के माध्यम से वृद्धि की सहायता करते हुए अधिक राजकोषीय समेकन के नाजुक संतुलन कार्य को बनाए रखा. जहाँ राजकोषीय समेकन से संसाधन आबंटन में सुधार कर अर्थव्यवस्था का समग्र विकास संभव हो सकता है, वहीं लक्षित सार्वजनिक व्यय से, उच्च पूँजीगत व्यय और मध्यम वर्ग के लिए अधिक खर्च करने योग्य आय में कर की कटौती से प्रेरित वृद्धि के रूप में - एक सकारात्मक, वैविध्यपूर्ण विकास प्रक्रिया को गति प्रदान कर सकती है, जहाँ निवेश और उपभोग, दोनों की माँग विकास की सहायता करती है. यह विशेष रूप से ऐसे समय में जरूरी था जब क्षेत्रीय संकेतकों ने शहरी माँग में नरमी के लक्षण दिखाना शुरू कर दिया था. जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.4% तक कम करने का बजट रखा गया है, जबकि ₹11.2 लाख करोड़ का केंद्र सरकार का पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों (₹10.2 लाख करोड़) की तुलना में 10% अधिक है, और मध्यम वर्ग पर विशेष फोकस के साथ निजी आयकर सुधारों से कर-बोझ को कम करने के माध्यम से लगभग ₹1 लाख करोड़ अंतरित करने से खपत को बढ़ावा मिलेगा. हाल के कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की सुदृढ़ वृद्धि से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजकोषीय समेकन और व्यय की गुणवत्ता में सुधार का संमिश्रण वृद्धि में सहायक रहा है.

## 1.3 कृषि में सुदृढ़ वृद्धि ने ग्रामीण माँग को बढ़ावा दिया

कृषि और संबद्ध गतिविधियों में सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) ने वित्तीय वर्ष 2025 में 4.6% की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जिसे खाद्यान्नों और बागवानी दोनों के उत्पादन में मजबूत वृद्धि का सहारा मिला (चित्र 1.2). कृषि वर्ष 2024 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन और बागवानी उत्पादन में धीमी वृद्धि और पिछले तीन वर्षों के दौरान कमजोर रबी खाद्यान्न उत्पादन देखने के बाद, सभी तीनों खंडों में कृषि वर्ष 2025 में इस गतिविधि की गति में तेज फेर-बदल ने कृषि वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र के वैविध्यपूर्ण विस्तार में योगदान दिया (चित्र 1.2). खेती से अर्जित औसत ग्रामीण घरेलू आय का लगभग पाँचवें हिस्से और पशुधन पालन से 7% (नाबार्ड के अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण, 2021-22 के अनुसार) के साथ, कृषि क्षेत्र के जीवीए में एक स्वस्थ वृद्धि ने ग्रामीण माँग को एक बड़ी उछाल दी. बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 3,677.2 लाख मीट्रिक टन (द्वितीय अग्रिम अनुमान) रहा, जो पिछले वर्ष के कुल उत्पादन 3,539.6 लाख मीट्रिक टन (तृतीय अग्रिम अनुमान) से अधिक है.

### चित्र 1.2: कृषि और संबद्ध क्षेत्र जीवीए, खाद्यान्न, और बागवानी उत्पादन: वर्ष 2011-12 के मूल्यों पर वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)

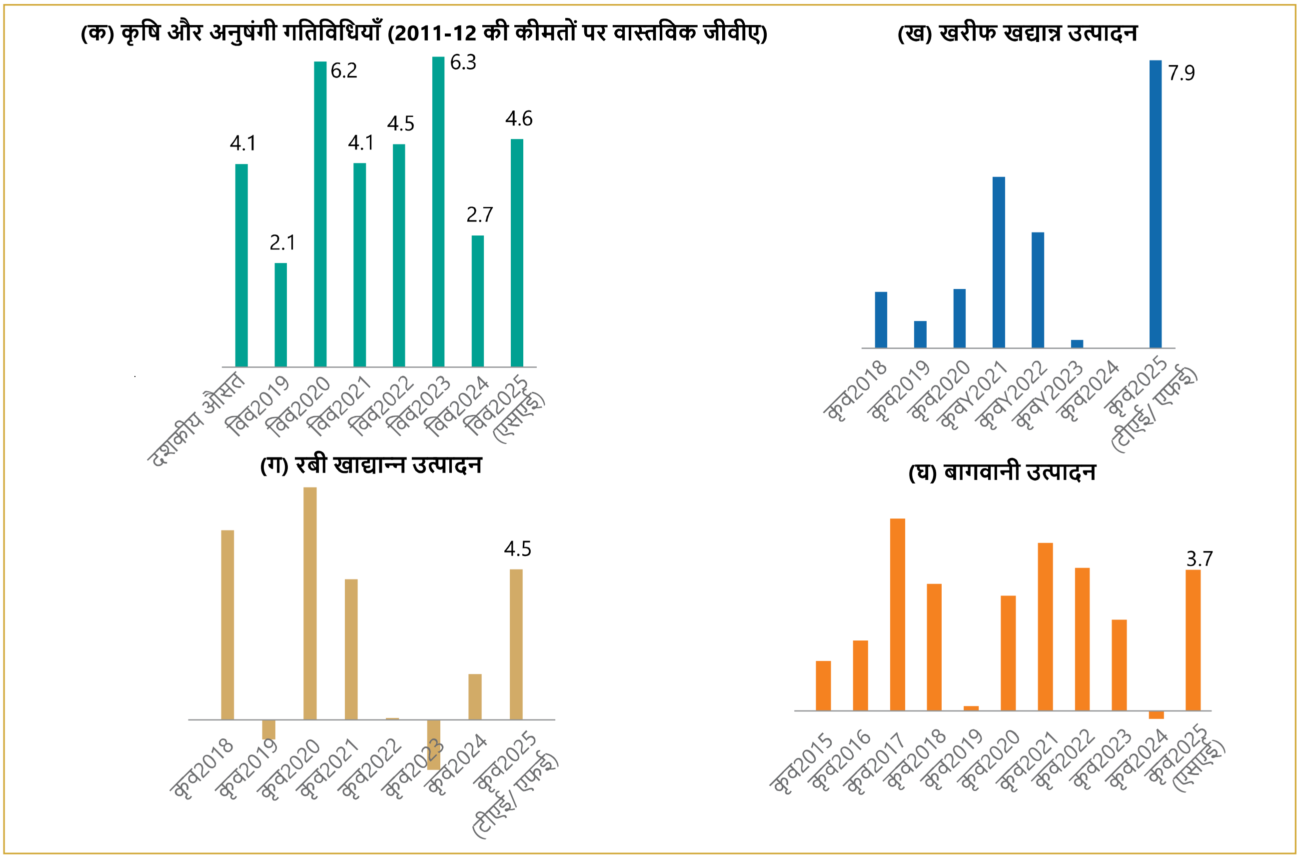


एफई = अंतिम अनुमान; जीवीए = सकल वर्धित मूल्य; एसएई = द्वितीय अग्रिम अनुमान; टीएई = तृतीय अग्रिम अनुमान; कृव = कृषि वर्ष; विव = वित्तीय वर्ष.

स्रोत:

- चित्र 1.2 (क): केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार.
- चित्र 1.2 (ख, ग, घ): कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार.

### 1.3.1 वर्ष के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति में तेज गिरावट

भारत की औसत उपभोग टोकरी में 45.86% हिस्सा खाद्य पदार्थों का है (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली वर्तमान उपभोग टोकरी के अनुसार). कम मुद्रास्फीति से न केवल समग्र मूल्य स्थिरता प्राप्त करने में मदद मिलती है, बल्कि आय की बेहतर क्रय शक्ति और अर्थव्यवस्था में संबंधित वास्तविक माँग बढ़ती है जिसके कारण मजबूत वृद्धि संभव होती है. वर्ष के उत्तरार्ध के दौरान, अक्तूबर 2024 में 9.7%

की खाद्य मुद्रास्फीति नरम होकर मार्च 2025 में 2.9% हो गई, किंतु वित्तीय वर्ष 2025 के लिए औसत खाद्य मुद्रास्फीति 6.7% के उच्च स्तर पर बनी रही. पिछले छह वर्षों में से गत पाँच वर्षों में, औसत वार्षिक खाद्य मुद्रास्फीति 6% या उससे अधिक ही रही, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि फसल पैदावार बढ़ाने, मूल्य-वृद्धि को कम करने और खाद्य पदार्थों की बर्बादी कम करने के लिए खाद्य आपूर्ति शृंखलाओं में सुधार करने के लिए निरंतर उपाय करने की जरूरत है (चित्र 1.3).

## चित्र 1.3: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खाद्य मुद्रास्फीति

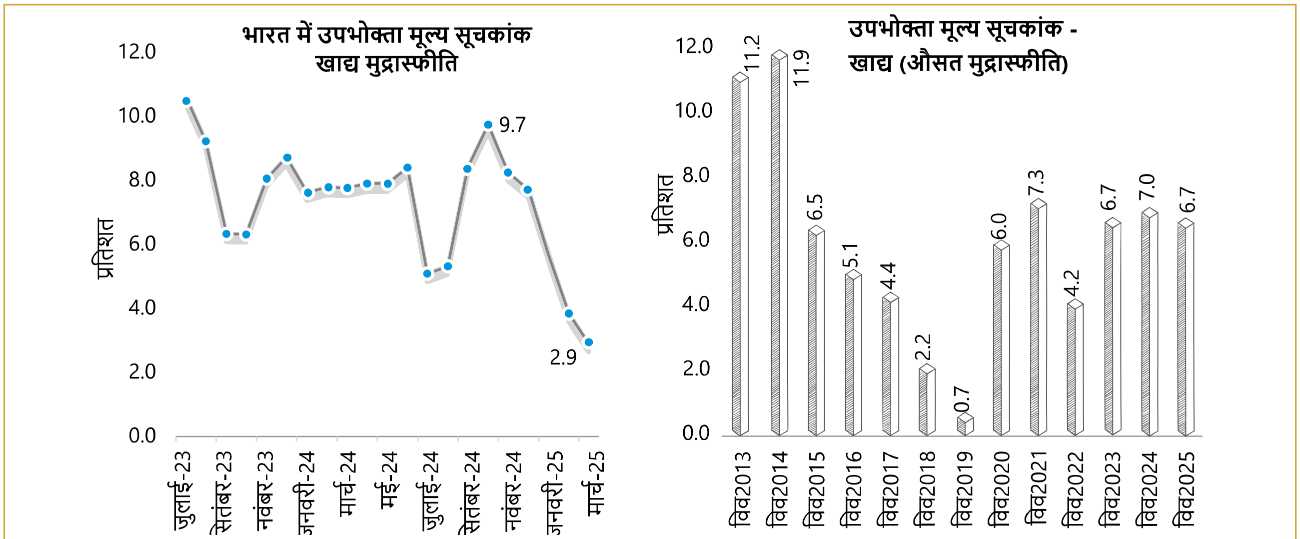


स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक

वर्ष 2011-12 से भारतीय परिवारों का औसत उपभोग क्रम बदल गया है, जैसा कि अगस्त 2022 से जुलाई 2023 की अवधि से संबंधित घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस, 2022-23), जिसे 11 वर्षों के अंतराल के बाद जारी किया गया था और बाद के अगस्त 2023 से जुलाई 2024 की अवधि से संबंधित सर्वेक्षण (एचसीईएस 2023-24) के निष्कर्षों से स्पष्ट हो जाता है. जहाँ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2022-23 में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी में काफी कमी आई, वहीं वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में इनके तदनुरूपी हिस्सों में मामूली वृद्धि हुई, जो यह दर्शाता है कि जब खाद्य मुद्रास्फीति उच्च बनी रहती है, तो घरेलू उपभोग का एक बड़ा हिस्सा (दी गई व्यय-योग्य आय के लिए) खाद्य पदार्थों के लिए आबंटित किया जाता है. अत:, औसत उपभोग टोकरी में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी वर्ष 2023-24 में भी उच्चतर रहने के कारण, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जन्य वृद्धि से भिन्न वृद्धि के लिए आपूर्ति-पक्ष के उपाय महत्वपूर्ण बने रहेंगे.

## तालिका 1.2: प्रतिव्यक्ति मासिक उपभोग - व्यय में अनाजों/ खाद्य पदार्थों का हिस्सा

| | ग्रामीण | | शहरी | |
|---|---|---|---|---|
| *अवधि* | *अनाज* | *खाद्य पदार्थ* | *अनाज* | *खाद्य पदार्थ* |
| 1999-2000 | 22.2 | 59.4 | 12.4 | 48.1 |
| 2004-05 | 17.5 | 53.1 | 9.6 | 40.5 |
| 2009-10 | 13.8 | 57.0 | 8.2 | 44.4 |
| 2011-12 | 10.8 | 52.9 | 6.7 | 42.6 |
| 2022-23 | 4.9 | 46.4 | 3.6 | 39.2 |
| 2023-24 | 5.0 | 47.0 | 3.8 | 39.7 |

एमपीसीई = मासिक प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय.

स्रोत: एनएसएसओ (2024), घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण: 2023-24, एनएसएस रिपोर्ट सं. 592, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार.

### 1.3.2 कृषि ऋण प्रवाह में निरंतर उच्च वृद्धि से फलता-फूलता कृषि क्षेत्र

प्राथमिकता क्षेत्र मानदंडों के अंतर्गत कृषि को ऋण के लक्षित प्रवाह को अनिवार्य रूप से प्राप्त करने और केसीसी के सैचुरेशन अभियान के माध्यम से केसीसी लाभार्थियों का समग्र कवरेज करने हेतु सरकार के निरंतर नीतिगत बल से कृषि ऋण गहनता में लगातार वृद्धि हुई है. जहाँ, हाल के कुछ वर्षों से लगातार, कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों से अधिक की उपलब्धि हुई है, वहीं महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेश ऋण (मीयादी ऋण) का हिस्सा भी उत्तरोत्तर बढ़ा है और अब 40% से भी अधिक हो गया है, जिससे फसल की पैदावार और मूल्य वर्धन दोनों में वृद्धि हुई है. वित्तीय वर्ष 2025 में, ₹27.5 लाख करोड़ के लक्ष्य के समक्ष, फसल उत्पादन और कृषि क्षेत्र में निवेश, दोनों के लिए कृषि ऋण का वास्तविक संवितरण ₹28.7 लाख करोड़ था. वार्षिक कृषि जीवीए के प्रतिशत के रूप में कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह के रूप में परिभाषित की जाने वाली, ऋण गहनता, जो मौजूदा सदी की शुरुआत में लगभग 10% थी अब बढ़कर 50% से भी अधिक हो गई है (चित्र 1.4). संशोधित ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत ब्याज की दरों में सहायता प्राप्त करने हेतु केंद्रीय बजट 2025-26 में केसीसी की सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रति उधारकर्ता संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण की सीमा को ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख करने के साथ, ऋण की गहनता में बढ़त जारी रहने की उम्मीद की जा सकती है.

चित्र 1.4: कृषि हेतु ऋण प्रवाह

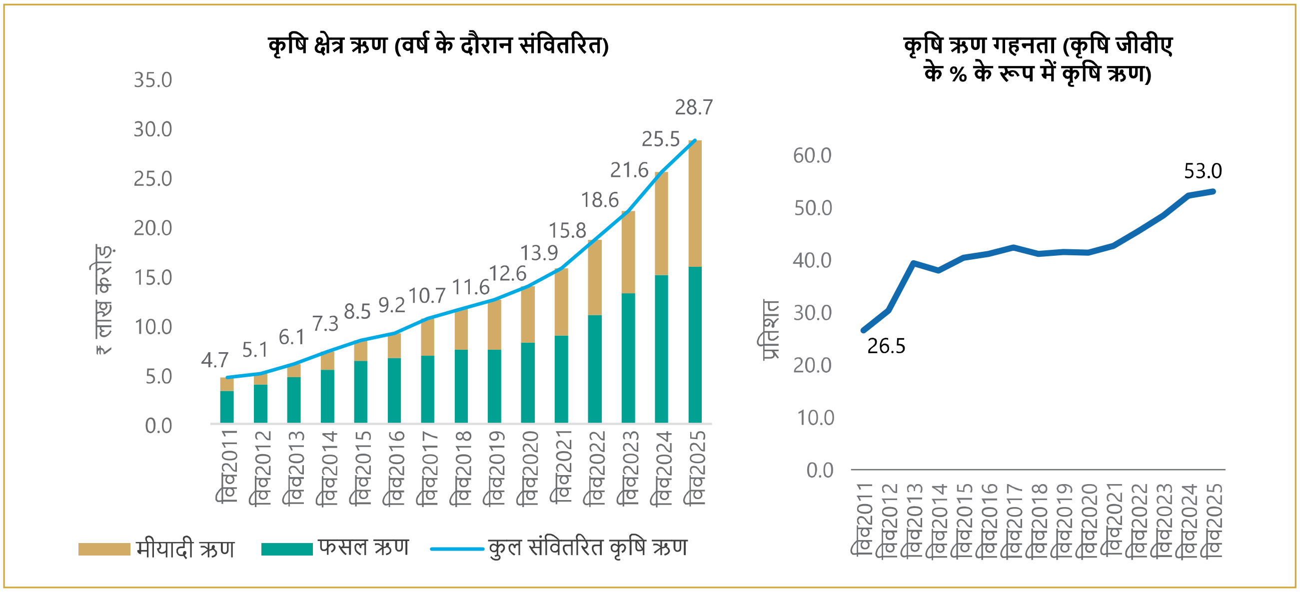


स्रोत: नाबार्ड

## 1.4 ग्रामीण आर्थिक गतिविधि जीवंत बनी रही

आर्थिक गतिविधियों के अनेक संकेतकों ने वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत उपभोग-आधारित वृद्धि दर्शाई. तेज़ी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं (एफएमसीजी) की मात्रात्मक वृद्धि, शहरी क्षेत्रों में देखी गई मंद गति से न केवल अधिक हो गई, बल्कि वित्तीय वर्ष 2025 की एक के बाद एक तिमाहियों में नियमित रूप से बढ़ती गई, जबकि अंतिम तिमाही में मामूली रूप से मंद पड़ गई (चित्र 1.5). नाबार्ड के द्विमासिक ग्रामीण आर्थिक स्थिति और प्रवृत्ति सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण परिवारों का उपभोग व्यय सर्वेक्षण के सभी पाँचों चरणों (सितंबर 2024, नवंबर 2024, जनवरी 2025, मार्च 2025 और मई 2025 में आयोजित) के दौरान अति उत्साहवर्धक रहा, जिनमें से अधिकांश लोगों (मार्च 2025 में 79.1%) ने यह बताया है कि उन्होंने पिछले एक वर्ष (यानी, सर्वेक्षण के दौर में उनके भाग लेने की अवधि से 12 माह पहले) के दौरान अपने उपभोग व्यय में वृद्धि का अनुभव किया है.

## चित्र 1.5: 2024-25 में ग्रामीण उपभोग माँग

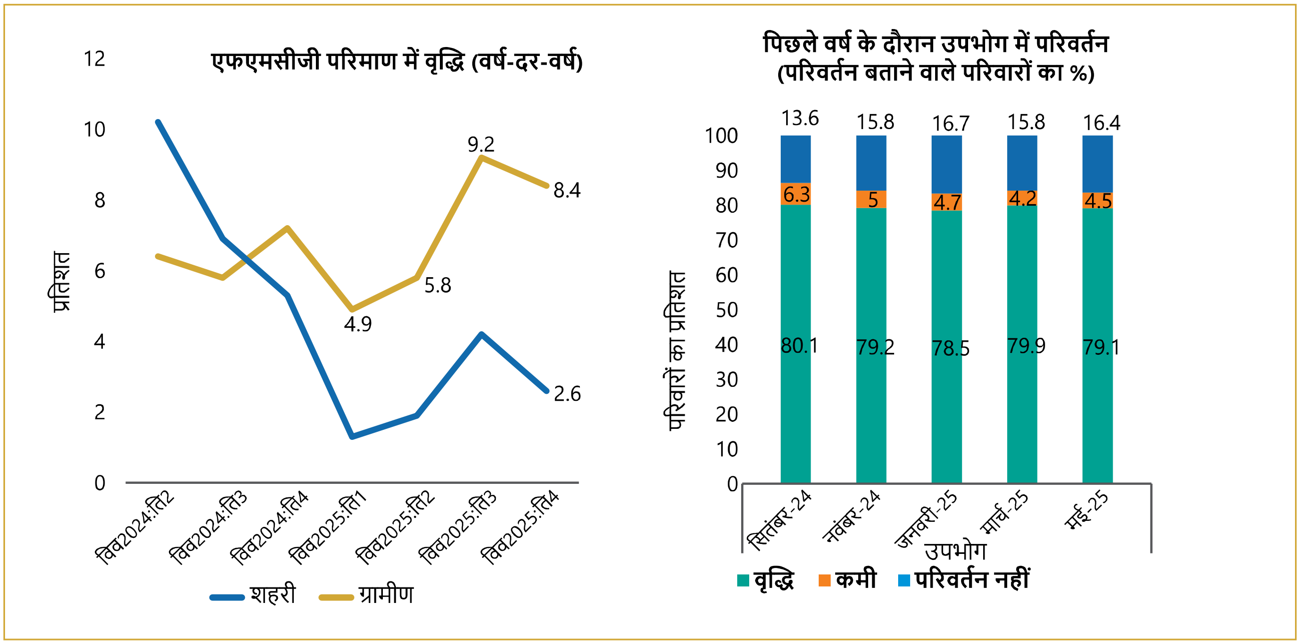


स्रोत: एनआईईएलएसईएनक्यू और नाबार्ड

महत्वपूर्ण यह रहा कि, कुल परिवारों में से उन परिवारों, जिन्होंने अपनी खपत में गिरावट का अनुभव किया, सर्वेक्षण के पाँचों चरणों में उनकी हिस्सेदारी कम बनी रही (मई 2025 में मात्र 4.5%). अधिकांश परिवारों (50% से भी अधिक) ने भी लगातार यह बताया है कि वे अगली तिमाही के दौरान अपनी आय और रोज़गार की स्थिति में सुधार की उम्मीद करते हैं (चित्र 1.6).

## चित्र 1.6: ग्रामीण परिवारों की प्रवृत्तियाँ - आय और रोज़गार (अगली तिमाही में प्रत्याशित परिवर्तन)

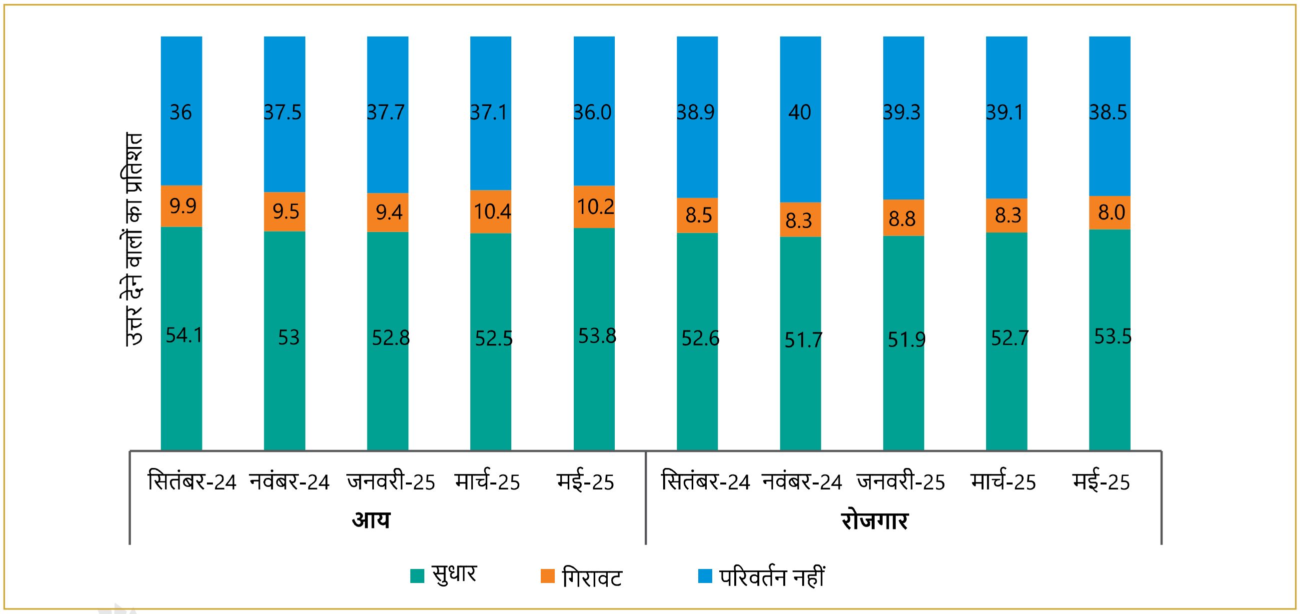


स्रोत: नाबार्ड

अलग-अलग रूप से अनेक उच्च-आवृत्ति (मासिक) वाले संकेतकों में परिवर्तनों का आकलन करते हुए और ग्रामीण आर्थिक गतिविधि के मिश्रित सूचकांक तैयार कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति का पता लगाया जा सकता है. इन संकेतकों की सूची में स्कूटरों, उर्वरकों और ट्रैक्टरों की बिक्री, कृषि और कृषीतर रोज़गार, कृषि निर्यात, कृषि के लिए बैंक का ऋण प्रवाह, मनरेगा की माँग, ग्रामीण मज़दूरी, व्यापार की स्थिति (यानी, थोक मूल्य सूचकांक से प्राप्त खाद्येतर कीमतों के समक्ष खाद्य-पदार्थों की कीमतों का अनुपात), जलाशयों का जल-स्तर (जो फसल की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है), और ग्रामीण प्रवृत्ति (सीएमआईई सर्वेक्षण के अनुसार) शामिल रहते हैं. मौद्रिक संकेतकों (जैसे कृषि निर्यात, कृषि ऋण और ग्रामीण मजदूरी) को सीपीआई-ग्रामीण मुद्रास्फीति द्वारा अवस्फीत किया जाता है ताकि संकेतकों के बीच तुलनीयता सुनिश्चित की जा सके. वित्तीय वर्ष 2024 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025 में प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, सबसे पहले प्रत्येक संकेतक के लिए बारह-माह के औसत मूल्य निकाले जाते हैं, फिर इन वार्षिक औसत मूल्यों के लिए विकास की दर का अनुमान लगाया जाता है. इस दृष्टिकोण के अनुसार, अनेक संकेतकों ने वित्तीय वर्ष 2025 में मजबूत वृद्धि प्रदर्शित की (चित्र 1.7). यहाँ यह ध्यान दिया जाए कि मनरेगा के तहत रोज़गार में गिरावट और कृषि में रोज़गार, कृषीतर रोज़गार में विस्तार के साथ मेल खाता है, और इसलिए, ये सभी तीन संकेतक एक साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार की ओर इशारा करते हैं.

चित्र 1.7: ग्रामीण गतिविधि संकेतक (विव 2024 की तुलना में विव 2025 के औसत मूल्यों में % परिवर्तन)

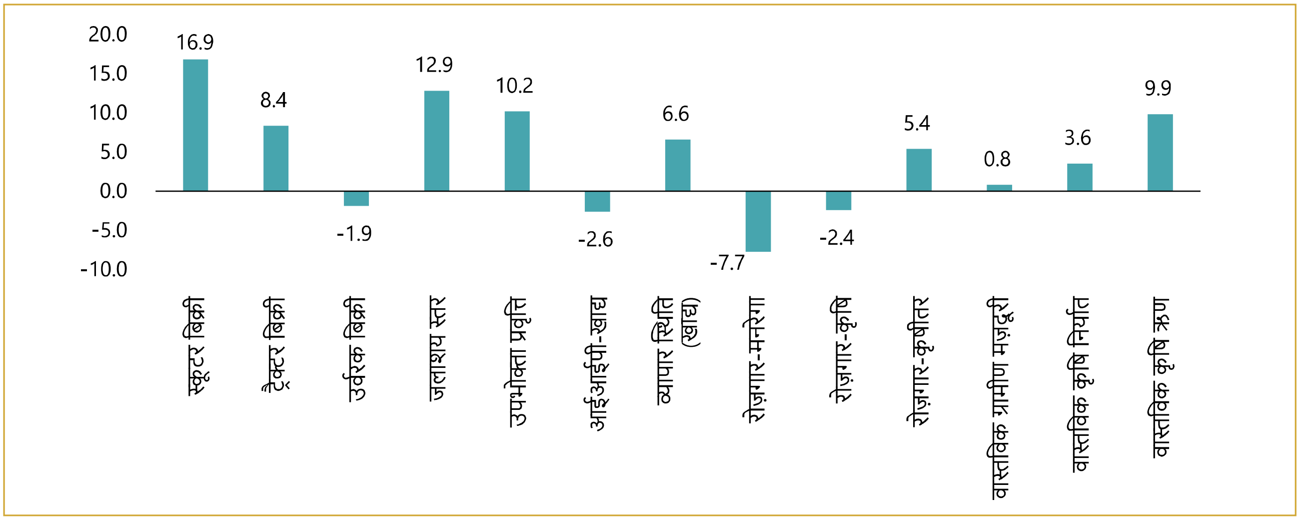


जब उच्च आवृत्ति वाले बहुसंख्य संकेतक विपरीत दिशा में चलते हैं, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति के लिए उनका सापेक्ष महत्व अधिक स्पष्ट नहीं होता है, तो एक मिश्रित संकेतक तैयार करने के लिए जानी-मानी आयाम में कमी करने की तकनीक, यथा प्रमुख घटक विश्लेषण (पीसीए), का प्रयोग किया जा सकता है. भारत के लिए ग्रामीण आर्थिक गतिविधि के मिश्रित संकेतक से यह पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2025 के उत्तरार्ध में ग्रामीण आर्थिक गतिविधि की गति हल्की सी कमी के साथ उत्साहजनक रही (चित्र 1.8).

चित्र 1.8: ग्रामीण आर्थिक गतिविधि का मिश्रित संकेतक (मार्च 2025)

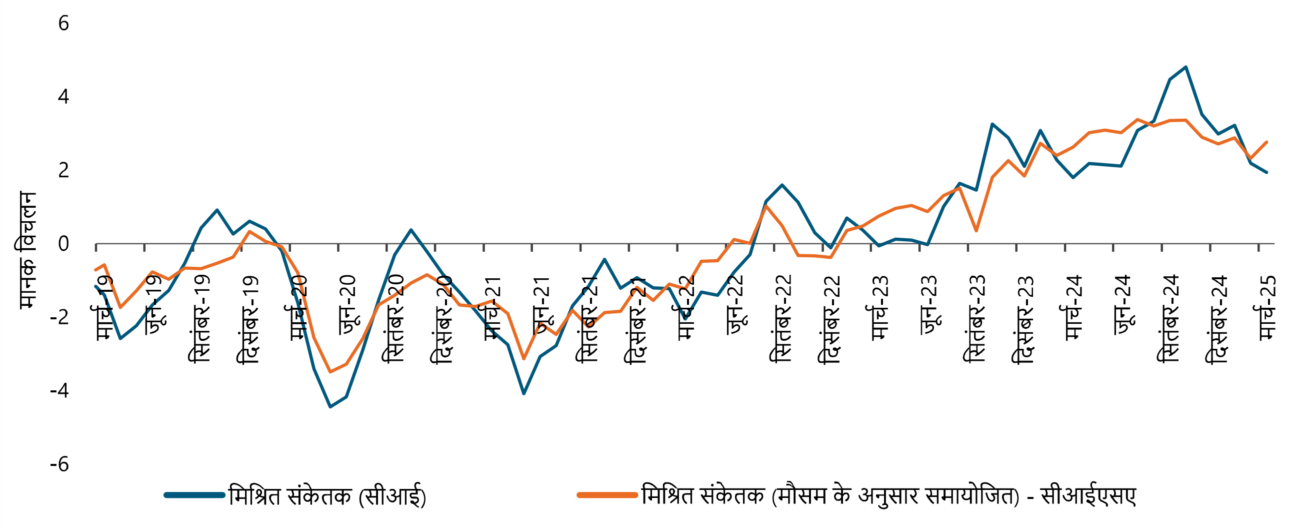


स्रोत: नाबार्ड

नोट: चूँकि अंतर्निहित चर विषम हैं, अत: उन्हें (प्रत्येक को शून्य माध्य और इकाई विचरण के साथ) पहले मानकीकृत किया जाता है. अतः, सूचकांक के उच्च/ निम्न मान, मानक विचलनों के संदर्भ में औसत मान से ऊपर/ नीचे होते हैं. चूँकि मासिक आँकड़ों में अक्सर मौसम का तत्व निहित होता है, इसलिए मौसम के अनुसार समायोजित मिश्रित सूचकांक तैयार करने के लिए भी उन्हें मौसम से परे किया जाता है.

### 1.4.1 नीतिगत पहलें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रूपांतरकारी परिवर्तन लाती हैं

यह स्वीकार करते हुए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियाँ, जटिल किंतु आपस में जुड़ी हुई होती हैं, सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रूपांतरकारी परिवर्तन लाने के लिए एक बहुआयामी नीतिगत दृष्टिकोण अपनाया गया. हाल के कुछ प्रमुख नीतिगत सहयोग तालिका अ1.1 में दिए गए हैं. इन पहलों का सामूहिक ध्येय गरीबी को कम करना, किसानों की आय बढ़ाना, जलवायुगत आघातों के प्रति अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना, कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी और आधुनिक फसल प्रथाओं का अंगीकरण बढ़ाना, विपणन आधारभूत संरचनाओं और ग्रामीण आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ बनाना, डिजिटल आधारभूत संरचनाओं की संभाव्यताओं का उपयोग बढ़ाना और वित्तीय समावेशन को गहराई तक ले जाना है. वित्तीय वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट में, कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने के लिए अनेक विशिष्ट उपायों की घोषणा की गई (बॉक्स अ1.1).

## 1.5 समष्टिगत आर्थिक दृष्टिकोण

हाल के वर्षों में भारत का सुदृढ़ विकास का प्रदर्शन, इसकी सुदृढ़ समष्टिगत आर्थिक नीतियों और पूर्वकालिक संरचनात्मक सुधारों का परिणाम रहा है, किंतु वर्ष 2047 तक एक उन्नत अर्थव्यवस्था बनने का परिकल्पित दर्जा प्राप्त करने के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की अपेक्षित दर, इससे भी उच्चतर होगी, जिसके लिए देश की विकास क्षमता को बढ़ाने के लिए विकासोन्मुख नीतियों पर निरंतर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है. वित्तीय वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट में, विकसित भारत के गंतव्य को प्राप्त करने के लिए विकास के चार शक्तिशाली संवाहकों, नामतः कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात के लिए ईंधन के रूप में सुधारों पर जोर दिया गया है. संसाधनों के गलत आबंटन को कम करने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और नवोन्मेषों को सहयोग प्रदान करने की नीतियाँ देश की मध्यावधि विकास क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होंगी. तथापि, निकट भविष्य में, संरक्षणवादी प्रशुल्कों में वृद्धि और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के बढ़े हुए स्तरों से भारत का विकास दृष्टिकोण प्रभावित हुआ है, जो विकास के चार संवाहकों में से दो नामतः निर्यात और निवेश पर सीधा प्रभाव डाल सकता है.

विश्व व्यापार संगठन के आकलन के अनुसार अब 2025 में वैश्विक व्यापार वृद्धि संकुचित हो रही है. उत्तरी अमेरिका को आयात में 9.6% तक के संकुचन का सामना करना पड़ सकता है. भारत के लिए निर्यात का प्रमुख बाज़ार होने के कारण भारत को, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते का शीघ्र निष्पादन और/ या वैश्विक स्तर पर टैरिफ के तनावों का समाधान, भारत की निर्यात संभावनाओं में सुधार के लिए महत्वपूर्ण होगा. सेवाओं के उत्साहवर्धक निर्यात, और भारत के लिए माल निर्यात के लिए नए अवसरों का उपलब्ध होना इस बात पर निर्भर करेगा कि अन्य देश अपनी टैरिफ संरचना का प्रतिकार या मोलभाव कैसे करते हैं, हालाँकि, भारत की निर्यात और वृद्धि की संभावनाओं पर वैश्विक व्यापार में होने वाले किसी भी संकुचन का प्रतिकूल प्रभाव सीमित ही हो सकता है. टैरिफों में वृद्धि की इस लहर के शुरू होने से पहले ही भारत में निजी निवेश की माँग कम हो रही थी, और अन्य देशों से भारत में आने वाले सस्ते आयात के संभावित जोखिमों, संभावित वैश्विक विकास की मंदी से स्पिलओवर को दर्शाती घरेलू माँग में संभावित नरमी, व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में कुछ क्षेत्रों में भारत द्वारा टैरिफ संरक्षण को कम करने की संभावना और अस्थिर वित्तीय बाजारों से निवेश की प्रवृत्ति उदासीन हो सकती है. भारत के एक तिहाई से अधिक माल निर्यात एमएसएमई से आते हैं और निर्यातों का करीब दसवाँ हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है, अगर समग्र वैश्विक व्यापार की स्थिति बिगड़ती है, तो कृषि और एमएसएमई भी अपनी संभावनाओं के लिए कुछ नकारात्मक जोखिम देख सकते हैं. हालाँकि, भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते का सफल निष्पादन वृद्धि के दृष्टिकोण से बड़ी उछाल है.

इस प्रतिकूल वैश्विक माहौल में, घरेलू समष्टि-आर्थिक नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट रूप से वृद्धि की सहायक बनी है. फरवरी 2025 से मुद्रास्फीति, जो 4% से भी नीचे चल रही थी, में तेज़ी से कमी आने के साथ, और वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमानित कम मुद्रास्फीति के चलते मौद्रिक नीति दर को संचयी रूप में 100 आधार बिंदु कम कर दिया गया है, प्रणाली स्तर की तरलता की स्थिति को प्रासंगिक तरलता प्रबंधन साधनों के उपयोग से एक निरंतर अधिशेष में बदल दिया गया है, और विनियमन को हटाने की नीति ने ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बल प्रदान किया है. वित्तीय वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट ने पूँजीगत व्यय पर जोर बनाए रखने और राज्यों को अपना पूँजीगत व्यय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने के साथ-साथ ₹1 लाख करोड़ की उपभोग माँग को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्रदान किया है, जो एक साथ मिलकर वृद्धि के लिए राजकोषीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं. भारत की विकास प्रक्रिया में सेवाओं का वर्चस्व होने के कारण, माल व्यापार के लिए प्रतिकूल बाह्य वातावरण समग्र विकास के लिए बहुत अधिक नकारात्मक जोखिम पैदा नहीं कर सकता है. पण्य कीमतों में नरमी, जो कमज़ोर वैश्विक माँग दर्शाती है और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा अनुमानित सामान्य से अधिक मानसून से वैश्विक व्यापार और वृद्धि में किसी भी मंदी के प्रतिकूल प्रभाव की भरपाई होने की संभावना है. भारतीय कॉर्पोरेट घरानों और वित्तीय क्षेत्र की प्रमुख संस्थाओं के मजबूत तुलन-पत्रों से भी विकास की प्रक्रिया की सुदृढ़ता को बनाए रखने में सहायता मिलनी चाहिए. जोखिमों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2025-26 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का आकलन औसतन 3.7% पर किया है, जिसमें अनुमानित जीडीपी वृद्धि 6.5% आँकी गई है. वृद्धि और मुद्रास्फीति के इस संतुलन से समग्र समष्टिगत वित्तीय स्थिरता के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत की वैश्विक स्थिति को बनाए रखने में मदद मिलने की संभावना है.

वित्तीय वर्ष 2025 में ग्रामीण माँग में उछाल और कृषि क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन ने शहरी माँग के कमजोर होने और विनिर्माण के क्षेत्र में धीमी वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव को सीमित रखने में सहायता की थी. वित्तीय वर्ष 2026 में समग्र गैर-स्फीतिगत वृद्धि के लिए समान स्तर की सहायता को बनाए रखने के लिए, बजट में घोषित प्रमुख सुधारों को लागू करना महत्वपूर्ण होगा, जिसमें 100 आकांक्षी जिलों, जहाँ विकास की संभाव्यताएँ अप्रयुक्त रह गई हैं, पर विशेष ध्यान दिया जाना, जलवायु अनुकूलता बढ़ाना, खाद्य तेलों और दलहनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सब्जियों की आपूर्ति शृंखलाओं में सुधार, प्रौद्योगिकी और आधुनिक फसल पद्धतियों को अपनाने के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना, और अधिक से अधिक कृषीतर रोज़गार के अवसर पैदा करना शामिल हैं. अनुकूल मानसून और प्राथमिकता क्षेत्र ऋणीकरण मानदंडों और लक्षित वित्तीय समावेशन के उपायों के माध्यम से कृषि के लिए सुनिश्चित ऋण का पर्याप्त प्रवाह इस क्षेत्र के लिए अनुकूल स्थितियाँ उपलब्ध कराता है. तथापि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वर्ष के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति, यदि आवश्यक हुआ तो, आपूर्ति पक्ष के सामयिक उपायों के माध्यम से नियंत्रित रहे ताकि घरेलू प्रतिकूल आपूर्ति आघात के कारण विकास और समष्टिगत स्थिरता में व्यवधान से बचा जा सके. ग्रामीण मुद्रास्फीति में गिरावट और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सरकार से राजकोषीय अंतरण, दोनों ने ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद की है, किंतु टिकाऊ आधार पर ग्रामीण आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए ग्रामीण एमएसएमई, स्टार्ट-अपों, ग्रामीण आवासन, ई-कॉमर्स और स्थानीय नवोन्मेषों को प्रोत्साहित कर पर्याप्त कृषीतर रोजगार के अवसर पैदा करने पर नीतिगत बल को बनाए रखना और साथ ही अधिक व्यावसायिक दक्षता और उत्पादकता के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) को व्यापक रूप से अपनाने से रोजगार के लिए संभावित जोखिम को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण होगा.

# अध्याय 1 का परिशिष्ट

## तालिका अ1.1: कृषि क्षेत्र में रूपांतरकारी नीतिगत परिवर्तन

| क्रम सं. | योजना का नाम | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 01. | बाज़ार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस) | सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 सीज़न से बाज़ार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के अंतर्गत विभेदक मूल्य भुगतान का एक नया घटक प्रस्तुत किया है ताकि खराब होने वाली फसलों के किसानों को बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर का सीधे भुगतान किया जा सके. राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को फसल की भौतिक खरीद या किसानों को एमआईपी और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान करने का विकल्प होता है. यह खराब होने वाली फसलों के किसानों को चरम आवक अवधि के दौरान बम्पर फसल होने की स्थिति में गरजू बिक्री से बचाने के लिए शुरू किया गया था, जब कीमतें उत्पादन लागत से भी नीचे गिर जाती हैं. इसके अतिरिक्त, एमआईएस के तहत एक नई सुविधा भी शामिल की गई है, जिसके तहत अधिशेष उत्पादक राज्यों से, उपभोक्ता बाजारों में ले जाए जाने पर टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) की फसलों के भंडारण और परिवहन लागत के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों को प्रतिपूर्ति की जा सकती है जिससे किसान कल्याण और बाज़ार स्थिरता सुनिश्चित हो सके. |
| 02. | संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) | संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) के तहत, सब्सिडी युक्त केसीसी ऋणों की सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है. साथ ही, संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण सीमा को भी प्रति उधारकर्ता ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया गया है. ये परिवर्तन वित्तीय समावेशन को मजबूत करेंगे, कृषि क्षेत्र की सहायता करेंगे और ऋण-संचालित आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे, जो संधारणीय कृषि के सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप है. |
| 03. | नमो ड्रोन दीदी | यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराना है, जिसमें ड्रोन और सहायक उपकरण/ सहायक प्रभारों की लागत के 80% की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है, जो अधिकतम ₹8.0 लाख तक हो सकती है. स्वयं-सहायता समूहों के क्लस्टर स्तरीय फ़ेडरेशन (सीएलएफ) कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत ऋण के रूप में शेष राशि (खरीद की कुल लागत में से सब्सिडी घटाकर) जुटा सकते हैं, और क्लस्टर स्तरीय फ़ेडरेशनों को एआईएफ ऋण पर 3% की दर से ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी. |
| 04. | डिजिटल कृषि मिशन | सरकार ने भारतीय कृषि के लिए एक मजबूत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने, फसलों से संबंधित सटीक जानकारी तक समय पर पहुँच सुनिश्चित करने और किसान-केंद्रित डिजिटल नवोन्मेषों के विकास को बढ़ावा देने के लिए कुल ₹2,817 करोड़ के आबंटन के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है. इस मिशन का उद्देश्य कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत संरचना (डीपीआई) विकसित करना है, जिसमें एग्रिस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और एक व्यापक मृदा उर्वरता और प्रोफ़ाइल मानचित्र जैसे प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं. एग्रीस्टैक डीपीआई राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मेंटेन की जा रही तीन मुख्य रजिस्ट्रियों पर निर्मित है - भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र, फसल बुआई रजिस्ट्री और किसान रजिस्ट्री. मिशन के लक्ष्यों के एक भाग के रूप में, सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2027 तक देश भर में 11 करोड़ किसानों के लिए किसान आईडी बनाना और खरीफ 2025 से प्रारंभ करते हुए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण लागू करना है. |
| 05. | स्टार्ट-अपों और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि (एग्रीश्योर) | ग्रामीण नवोन्मेष और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अपों और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि (एग्रीश्योर) के नाम से ₹750 करोड़ की एक श्रेणी-II की वैकल्पिक निवेश निधि स्थापित की गई. इस मिश्रित पूँजी निधि में कृषि और किसान कल्याण विभाग और नाबार्ड, प्रत्येक द्वारा ₹250 करोड़ शामिल किए गए हैं, साथ ही वित्तीय संस्थाओं से ₹250 करोड़ अतिरिक्त जुटाए गए हैं. नाबार्ड की सहायक कंपनी नैबवेंचर्स के तहत प्रबंधित की जाने वाली इस निधि का उद्देश्य कृषि मूल्य शृंखला में स्केलेबल कृषि-आधारित स्टार्ट-अपों और ग्रामीण उद्यमों को सहायोग प्रदान करना है. |
| 06. | ई-एनडब्ल्यूआर आधारित गिरवी वित्तपोषण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस-एनपीएफ) | गरजू बिक्री को कम करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों (ई-एनडब्ल्यूआर) आधारित गिरवी वित्तपोषण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस-एनपीएफ) शुरू की, जिसमें किसानों के लिए फसलोपरांत वित्तपोषण को सहयोग प्रदान करने के लिए ₹1,000 करोड़ की समूह निधि आबंटित की गई है. इस योजना के अंतर्गत, किसान ई-एनडब्ल्यूआर द्वारा समर्थित भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) से मान्यता प्राप्त भांडागारों में भंडार कर रखी गई अपनी उपज को गिरवी रखके ऋण प्राप्त कर सकते हैं. |

### बॉक्स अ1.1: केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 2026 में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए घोषित उपायों की मुख्य बातें

1. **प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना:** वर्तमान योजनाओं के अभिसरण और लक्षित सहयोगों के माध्यम से, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण निष्पादन जैसी विशेषताओं वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा. इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं (1) कृषि उत्पादकता को बढ़ाना; (2) फसल विविधीकरण और संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना; (3) पंचायत और ब्लॉक स्तरों पर फसलोपरांत भंडारण का विस्तार करना; (4) सिंचाई आधारभूत संरचना में सुधार लाना; और (5) दीर्घावधि और अल्पावधि ऋण तक पहुँच को सुगम बनाना. इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की संभावना है.

2. **दलहनों में आत्मनिर्भरता:** सरकार द्वारा 6-वर्षीय 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' शुरू किया जाएगा, जिसमें अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

3. **सब्जियों और फलों के लिए वृहद् कार्यक्रम:** उत्पादन को बढ़ावा देने, आपूर्ति शृंखलाओं को सुव्यवस्थित करने, प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में एक नई पहल शुरू की जाएगी.

4. **उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन:** इस मिशन के तहत (i) अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने; (ii) उच्च उपज देने वाली, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु-अनुकूल बीज किस्मों का लक्षित विकास और प्रसार; और (iii) जुलाई 2024 से, 100 से अधिक बीज की किस्मों की व्यावसायिक उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

5. **कपास उत्पादकता मिशन:** कपास की खेती में उत्पादकता और संधारणीयता बढ़ाने के लिए पंच-वर्षीय पहल, जिसमें अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास पर विशेष जोर दिया जाएगा. किसानों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

6. **ग्रामीण समृद्धि और सुदृढ़ता का निर्माण:** कौशल उन्नयन, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में बेरोजगारी को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय 'ग्रामीण समृद्धि और अनुकूलन क्षमता' कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.

7. **ग्रामीण क्रेडिट स्कोर:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और ग्रामीण आबादी की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर तंत्र विकसित किया जाएगा.

8. **भारत के ईईजेड में मत्स्यपालन का विकास:** भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (ईईजेड) और गहरे सागरों के मत्स्य संसाधनों के संधारणीय उपयोग के लिए सरकार द्वारा तंत्र तैयार किया जाएगा, जिसमें अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

9. **जल जीवन मिशन:** वर्ष 2019 से अब तक 15 करोड़ घरों - जो ग्रामीण भारत के 80% का प्रतिनिधित्व करते हैं, को पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध हो चुका है. शत प्रतिशत घरों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, इस मिशन को कुल परिव्यय में वृद्धि के साथ वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

10. **फसल जर्मप्लाज्म के लिए जीन बैंक:** भविष्य की खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों की भंडारण क्षमता के साथ एक द्वितीय जीन बैंक स्थापित किया जाएगा. यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, दोनों के संरक्षण प्रयासों को सहयोग प्रदान करेगा.